आरोप मोहनलाल माहेश्वरी की वसीयत छिपाने एवं बेचने का आरोप

अमानत में खयानत का अजूबा खेल, दान की राशि में हेरफेर

नवभारत न्यूज बालाघाट। शहर के सर्किट हाउस में एक अजूबी मामले की श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट, अंग्रेजी स्कूल ट्रस्ट तथा अग्रवाल समाज ने संयुक्त रूप पत्रकारों से चर्चा किया।

प्रेस को जानकारी देते हुए उक्त सभी ट्रस्टों के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में कई दानदाता पैदा हुए जिन्होंने अपना सबकुछ जन कल्याण में दान कर दिया है । ऐसे की एक दानदाता हुए जिन्होंने अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी अपने परिवार को ना देकर समाज ,मंदिर और गरीबों के कल्याण हाथ दान कर दिया । लेकिन उनके सपनों को साकार करने के बजाय उनके के कर्णधरो ने चकनाचूर कर दिया ओर दान के बजाय हरफेर कर संपत्ति ही बेच डाली । इस तरह अमानत में खयानत का मामला विश्वास में धोखा का सामने आया।

प्रेस वार्ता में बताया गया कि दानदाता मोहनलाल माहेश्वरी की वसीयत को छिपा कर कुछ लोगों ने लगभग 60 करोड की उक्त

संपत्ति का कुछ हिस्सा छल पूर्वक अन्यत्र लोगों को बेच भी दिया है। वसीयत छिपाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। साथ ही उच्च स्तरीय मामले की जांच कराएंगे।

30 वर्षों तक वसीयत छिपाई गयी

ट्रस्ट के लोगों ने स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी की 16 अगस्त 1996 की वसीयत से जुडा मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि वसीयत लगभग 30 वर्षों तक सार्वजनिक नहीं की गई। जिससे वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा का पालन नहीं हो सका और इस दौरान मंदिर ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में कथित रूप से ऐसे निर्णय लिए गए जिनसे कुछ लोगों को अनुचित आर्थिक लाभ मिला।

एफआईआर दर्ज कराएंगे

अब ट्रस्ट ने इस मामले में सुरजमल बोहरा और अनिल कांकरिया दोनों ही लोगों के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को केवल दीवानी विवाद तक सीमित नहीं रखेंगे ।संयुक्त निर्णय के अनुसार शीघ्र ही सक्षम पुलिस अधिकारियों के समक्ष विस्तृत आपराधिक शिकायत प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से तकनीकी एवं निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी।

सूरजमल को मिला था बंद लिफाफा

अधिवक्ता वर्णन श्रीवास्तव ने बताया कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने 16 अगस्त 1996 को वसीयत लिखी थी तथा उसे निष्पादित करने के लिये सुरजमल बोहरा को बंद लिफाफे में सौंपी थी। निर्देश दिये थे कि मेरी मृत्यु के बाद उसे मूल अवस्था में अनिल कांकरिया को सौंप देना। जहां विधिक नोटिसों के जवाब में सूरजमल बोहरा ने स्वीकार किया है कि स्वर्गीय मोहनलाल माहेश्वरी ने उन्हें एक बंद लिफाफा सौंपा था और निर्देश दिया था। वहीं अनिल कांकड़िया ने भी अपने लिखित उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उन्हें उक्त वसीयत सुरजमल बोहरा से मोहनलाल माहेश्वरी के निधन के बाद प्राप्त हुई थी।

वसीयत छिपाकर रखी गयी

ट्रस्टों का कहना है कि यदि वसीयत वर्ष 1996 से अस्तित्व में थी और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संबंधित व्यक्तियों के कब्जे में आ गई थी, तो फिर उसका समय पर क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया। उनका आरोप है कि वसीयत को लंबे समय तक जानबूझकर गुप्त रखा गया और संबंधित हितधारकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। ट्रस्टों का यह भी आरोप है कि इस अवधि में मंदिर ट्रस्ट की मूल्यवान संपत्तियों का विक्रयए अंतरण और अन्य वित्तीय लेन .देन किए गए। जिनसे कथित रूप से कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा।

60 करोड़ की संपत्ति का कुछ हिस्सा बेच दिया

ट्रस्ट पदाधिकारियों ने दावा किया है कि लगभग 60 करोड की उक्त संपत्ति का कुछ हिस्सा संबधितों के वारसानों के द्वारा मिलीभगत करछल पूर्वक अन्यत्र लोगों को बेच भी दिया है। ट्रस्ट ने मांग की है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा की अवहेलना नहीं बल्कि धार्मिक न्यास की संपत्तियों के साथ गंभीर विश्वासघात और समाज के साथ छल का मामला भी हो सकता है। ट्रस्टों ने दावा किया है कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर भारतीय न्याय संहिताकी विभिन्न धाराओं जैसे आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, बेईमानी से संपत्ति के दुरुपयोग तथा जालसाजी से संबंधित प्रावधानों के तहत जांच की आवश्यकता बनती है।

1160 करोड़ के चावल घोटाले की हो उच्चस्तरीय जांच

नवभारत न्यूज बालाघाट। मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चित बालाघाट जिले के कथित 1160 करोड़ रुपये के चावल घोटाले का मामला अब और अधिक गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने शुक्रवार को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अब मुख्य सचिव से मुलाकात किया ।

विधायक अनुभा मुंजारे ने मंत्री एवं मुख्य सचिव को अवगत कराया कि बालाघाट जिले में राइस मिलर्स एवं एथेनॉल प्लांट संचालकों द्वारा शासन के चावल के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं से जुड़ा यह मामला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि किसानों, गरीबों, महिलाओं, बच्चों , सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा शासन के वित्तीय हितों से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो शासन को हुए आर्थिक नुकसान के साथ-साथ आम जनता का विश्वास भी प्रभावित होगा।

अपने पत्र में विधायक ने कहा कि पूरे मामले की किसी सक्षम एवं स्वतंत्र एजेंसी अथवा उच्चस्तरीय समिति से जांच कराई जाए, ताकि बिना किसी दबाव के सभी तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण हो सके। उन्होंने विशेष रूप से मांग की कि बालाघाट से भेजे गए सभी 44 ट्रकों के परिवहन, दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कराई जाए। इसके साथ ही संबंधित एथेनॉल प्लांट, परिवहनकर्ताओं, राइस मिलों तथा वेयरहाउस संचालकों की भूमिका की भी विस्तृत जांच की जाए।

विधायक ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकरण के तार मध्य प्रदेश से बाहर महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश तक जुड़े होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए इन राज्यों से जुड़े संभावित नेटवर्क,वित्तीय लेन-देन, परिवहन श्रृंखला तथा संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं की भी गहन जांच की जाए, ताकि पूरे रैकेट का खुलासा हो सके। उन्होंने मांग की कि जांच में जो भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाए, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही शासन को हुई आर्थिक क्षति का वैज्ञानिक आकलन कर संबंधित दोषियों से पूरी राशि की वसूली भी की जाए। विधायक ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और वहां जनता की आवाज मजबूती से उठाना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बालाघाट जिले में हुए इस कथित चावल घोटाले की न्यायिक जांच कराई जाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलकों में भी इस मामले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एक नजर में

ग्राम पंचायत अर्जुनी के सचिव निलंबित

नवभारत कटंगी। ग्राम पंचायत अर्जुनी के सचिव डेविड रानाडे की लगातार लापरवाही और पंचायत से अनुपस्थित रहने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। समाचार प्रकाशित होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही कर दी है। ग्राम पंचायत अर्जुनी के सरपंच एवं ग्रामीणों ने सचिव पर नियमित रूप से पंचायत नहीं आने, विकास कार्यों की उपेक्षा करने तथा ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे। ग्रामीणों का कहना था कि सचिव वर्षभर में 365 दिनों में 65 दिन भी पंचायत नहीं पहुंचे, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे।

विधायक ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश- मामले की शिकायत क्षेत्रीय विधायक गौरव पारधी तक भी पहुंची थी। विधायक ने समीक्षा बैठक में सचिव की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। समाचार के प्रकाशन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कर सचिव डेविड रानाडे को निलंबित कर दिया।

120 मुस्लिम मेधावी छात्र-छात्राओं का 16 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

बालाघाट। मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चरल सोसायटी, बालाघाट द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 16 अगस्त 2026 (रविवार) को दोपहर 2 बजे अंजुमन शादी हॉल, बालाघाट में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 120 मुस्लिम छात्र-छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। सोसायटी ने बताया कि इस सम्मान समारोह का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करना तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा सभी चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। इस प्रकार के आयोजन से न केवल सम्मानित विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि अन्य छात्र-छात्राओं को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलती है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 137 पौधों का रोपण

नवभारत,खैरलाँजी। पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान को समर्पित 'एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला किन्ही में एक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 24 जुलाई को 137 पौधों का रोपण कर विद्यालय परिसर और आसपास हरियाली बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विद्यालय में यह सकारात्मक बदलाव उस समय से देखने को मिल रहा है जब प्रधान पाठक दामेन्द्र कुमार मन्दरेले ने 1 जुलाई को शाला का प्रभार

संभाला। प्रभार लेते ही उन्होंने विद्यालय में कई नवाचारों की शुरुआत की, जिससे शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों की दिनचर्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, प्रधान पाठक द्वारा एम डी एम (का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है और बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय में प्रार्थना सभा को भी व्यवस्थित किया गया है, जिसमें लाउडस्पीकर के माध्यम से गायन, प्रेरणादायक संदेश और बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है।

खेत गए दंपत्ति, पीछे से चोरों ने घर में रखे जेवर और नकदी की पार

अरंडिया में दिनदहाड़े वारदात, टूटे मिले संदूक और आलमारी के ताले

नवभारत, परसवाड़ा। थाना क्षेत्र के ग्राम अरंडिया में दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात ने ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेत में काम करने गए दंपती के सूने घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। घटना का पता तब चला जब गृहस्वामिनी दोपहर में

खाना लेने घर पहुंची।

पुलिस के अनुसार अरंडिया निवासी किसान लिखीराम बिसेन बुधवार सुबह खेत पर काम करने चले गए थे। कुछ देर बाद उनकी पत्नी भी घर में ताला लगाकर खेत पहुंच गईं। दोपहर करीब एक बजे जब वे घर लौटीं तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो आलमारी, संदूक और सूटकेस के ताले भी टूटे पड़े थे तथा पूरा सामान अस्त-व्यस्त था। पीड़ित परिवार ने जब सामान की जांच की तो पता चला कि घर में रखे दो मंगलसूत्र, दो जोड़ी झुमके, दो जोड़ी बालियां, सोने की तीन पत्ती, चांदी की दो जोड़ी पैरपट्टी, एक करधन तथा 15 हजार रुपए नकद गायब हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पीड़ित ने अपने रिश्तेदारों के साथ थाना परसवाड़ा पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूने मकान पर थी चोरों की नजर- प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुई। इस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। चोरों ने पहले मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और फिर घर के भीतर रखे बक्सों एवं आलमारी को खंगालकर कीमती सामान समेट लिया।

आबादी भूमि की रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा टैक्स : पारधी

मप्र उपकर अधिनियम1981 में हुए संशोधन से पहुंचेगा सीधे ग्रामीणों को लाभ

नवभारत कटंगी 24 जुलाई। मध्यप्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 में संशोधन पर चर्चा के दौरान कटंगी-खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारधी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।

उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया और कहा की राज्य सरकार ग्रामीण परिवारों को

उनकी आबादी की जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाने का काम कर रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 में संशोधन किया गया।

सेस पूरी तरह कर दिया खत्म-इस संशोधन के तहत स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला सेस (उपकर) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब गांवों के लाखों परिवार बिना इस अतिरिक्त शुल्क के अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और अपनी भूमि का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करने का रास्ता भी आसान होगा।

ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत- विधायक पारधी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लोगों को उनकी आबादी की जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। पहले इस रजिस्ट्री पर सेस (उपकर) देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। इससे ग्रामीण परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और वे बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे।

अब कानूनी स्वामित्व मिलेगा- उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास वर्षों से जमीन थी, लेकिन उसके वैध दस्तावेज नहीं थे, उन्हें अब कानूनी स्वामित्व मिलेगा। इससे भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा।

मिनिस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी का पट्टा निरस्त

पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

नवभारत बालाघाट। बालाघाट बस स्टैंड क्षेत्र स्थित नजूल भूमि पर पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के मामले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मृणाल मीना ने सख्त कार्रवाई करते हुए दी मिनिस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित, बालाघाट को आवंटित पट्टा निरस्त कर दिया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 20 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुसार संबंधित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने तथा भूमि पर शासन का आधिपत्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बस स्टैंड स्थित नजूल शीट क्रमांक-306, प्लॉट क्रमांक-277/3 की 122.075 वर्गमीटर (1314 वर्गफुट) भूमि सोसायटी को केवल कैंटीन संचालन के उद्देश्य से पट्टे पर आवंटित की गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि सोसायटी द्वारा स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत इस भूमि पर व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था, जो पट्टे की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण में यह भी सामने आया कि सोसायटी ने भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की। साथ ही निर्माण शुरू करने से पहले नजूल विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया। नगरपालिका से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करते समय भी पट्टे की शर्तों के उल्लंघन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए। जांच में यह भी पाया कि संबंधित भूमि पर कैंटीन का संचालन नहीं किया जा रहा था और न ही सोसायटी अपने पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कोई गतिविधि संचालित कर रही थी। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सोसायटी को कारण बताओ सूचना जारी कर स्पष्टीकरण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

बाघ दिवस पर मॉडल स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बालाघाट। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे बाघ संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में वन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम एवं कैरियर मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंजर) सौरभ शरणागत के निर्देशन में आयोजित हुआ।

कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को बाघ संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता एवं पर्यावरण संतुलन में बाघों की महत्वपूर्ण भूमिका की जानकारी दी गई। प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को बाघों के प्राकृतिक

आवासों के संरक्षण, मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व तथा वन संरक्षण के महत्व से अवगत कराया गया।

विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। इस अवसर पर विद्यालय के ईको क्लब के विद्यार्थियों के लिए बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण विषय पर लिखित प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को वन विभाग द्वारा शील्ड एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

लोक निर्माण विभाग का सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार

जामरापानी-आंजनबिहरी सड़क निर्माण में भारी अनियमितता से ग्रामीणो में रोष

नवभारत कटंगी 24 जुलाई। मुख्यमंत्री द्वारा भूमिपूजन की गई जामरापानी से आंजनबिहरी तक 8.30 किमी सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। करोड़ों की लागत से बन रही इस सड़क में ठेकेदार की मनमानी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण एस्टिमेट के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। ग्रामीणों और जनपद सदस्य ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा

सड़क निर्माण में मुरुम के स्थान पर मिट्टी डाली जा रही है। इसके लिए राजस्व एवं वन विकास निगम की भूमि से अवैध रूप से मिट्टी-खनन कर सामग्री लाई जा रही है।

शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं- स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते नियमों को दरकिनार कर कार्य किया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत के बाद भी राजस्व और वन विकास निगम विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

राजनीतिक संरक्षण की आशंका - ग्रामीणों ने ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण मिलने की भी आशंका जताई है। उनका आरोप है कि उपयंत्री की मिलीभगत से गुणवत्ताहीन सामग्री से सड़क बनाई जा रही है, जिससे कुछ ही समय में सड़क उखड़ जाएगी।

जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग- जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने कलेक्टर एवं पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और मानक के अनुसार सड़क निर्माण कराने की मांग की है।

आयोजन वीवीवीपी-2026 में किया था मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व

बालाघाट के सिद्धार्थ को फिर मिला पीएम से संवाद का मौका

नवभारत, बालाघाट। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के ग्राम मंझारा (भरवेली) निवासी नेशनल वॉलिंटियर सिद्धार्थ गेडाम का भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के समन्वय से आयोजित मेरा भारत विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीवीपी-2026 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत 26 जुलाई 2026 को देशभर से चयनित प्रतिभागियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष द्विपक्षीय संवाद आयोजित किया जाएगा। इस संवाद में प्रधानमंत्री सीमावर्ती एवं वाइब्रेंट गांवों में

युवाओं के अनुभव, युवा नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता, राष्ट्रीय एकता तथा 'विकसित भारत 2047' के विजन पर प्रतिभागियों से चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ गेडाम इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

विशेष उपलब्धि यह भी है कि बालाघाट, सिवनी, मंडला, नैनपुर एवं छिंदवाड़ा सहित इस क्षेत्र के पाँच जिलों में से राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले सिद्धार्थ गेडाम एकमात्र युवा प्रतिभागी हैं, जिसने पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है।

सिद्धार्थ गेडाम इससे पूर्व भी विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। उन्होंने विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभावशाली वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसकी व्यापक सराहना हुई थी। इसके अतिरिक्त बजट क्वेस्ट-2026 में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर उन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। वे मेरा भारत एवं भारत सरकार के विभिन्न युवा अभियानों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और जनभागीदारी कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता निभाते रहे हैं।

वीवीवीपी-2026 के अंतर्गत प्रतिभागी सीमावर्ती गांवों में स्थानीय समुदाय, सुरक्षा बलों एवं प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर ग्रामीण विकास, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा जनभागीदारी को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में चला व्यापक जनजागरूकता अभियान

नवभारत, बैहर (बालाघाट)। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, वारासिवनी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए बैहर विकासखंड में व्यापक जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय की निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ते हुए अधिक से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन सुनिश्चित करना रहा।

इस अभियान के अंतर्गत कार्यालय जन शिक्षा केंद्र (बीआरसी) बैहर में दीपेश कुमार जैन (टीजीटी हिन्दी) एवं अयाज

अंसारी (पुस्तकालय अध्यक्ष) ने बीआरसी, बीएसी तथा शिक्षकों की बैठक में नवोदय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, परीक्षा एवं विद्यालय की विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सभी शिक्षकों से अपने-अपने विद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए प्रेरित करने एवं समय-सीमा के भीतर आवेदन भरवाने का आग्रह किया।

इस दौरान पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में उपलब्ध निःशुल्क आवासीय शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, भोजन एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया गया।